नयी मंजिल बड़ी उम्मीदें

सम्मेलन कक्षों से लेकर खेल के मैदानों तक महिलाओं की मौजूदगी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है. कर्मठता और आत्मविश्वास से महिलाएं कामयाबी की नयी-नयी इबारतें लिख रही हैं. परंपरागत तौर पर जिन क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, उन क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी दखल से लोगों को अचंभित किया है. इसी बीच भारतीय वायुसेना से एक सुखद खबर आयी है, पहली बार चालक दल में शामिल सभी महिला सदस्यों ने एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर को उड़ाया. दल की प्रमुख फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज एमआई 17वी5 उड़ानेवाली पहली महिला पायलट बनीं. को-पायलट के रूप में झारखंड की अमन निधि और तीसरी क्रू फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में शामिल रहीं. इससे पहले मिग-21 'बाइसन' फाइटर जेट की उड़ान भरने के साथ लेफ्टिनेंट भावना कंठ देश के पहली महिला फाइटर पायलट बनी थीं. वैसे तो भारतीय सेनाओं से महिलाओं के जुड़ने के लिए मेडिकल, कानून, शिक्षण, सिग्नल और इंजीनियरिंग विधाओं समेत तमाम तरह के विकल्प हैं. लेकिन, चुनौती पूर्ण जिम्मेदारियों के लिए महिलाओं का आगे आना रोमांचक है, साथ ही अच्छे भविष्य के लिए शुभ संकेत भी. बीते दिनों सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं के लिए सैन्य पुलिस के रास्ते भी खोल दिये हैं. सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री ने बीते जनवरी माह में इस योजना को हरी झंडी दिखा दी थी. वर्तमान में थलसेना में महिलाओं की हिस्सेदारी 3.80 प्रतिशत, वायुसेना में 13.09 प्रतिशत और नौसेना में छह प्रतिशत है. सैन्य पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति महिला सशक्तीकरण की दिशा में निश्चित ही एक बड़ी पहल है. आधी आबादी की हिस्सेदारी सेना ही नहीं, अपितु सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए. महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में सामाजिक बुराई आज भी हमारे बीच मौजूद है, जिसके लिए आम जनमानस को चेतना होगा. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे प्रयासों को व्यापक रूप देने की जरूरत है. महिलाओं की कार्यस्थलों पर भागीदारी की स्थिति दर्शाती अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कामकाजी आबादी में 26.5 प्रतिशत का लैंगिक अंतराल मौजूद है. अगर 2025 तक वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल में डेढ़ प्रतिशत की भी कमी आती है, तो विश्व जीडीपी में 5.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त हो सकती है. जिस तरह से महिलाएं साहसिक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रही हैं, उससे पारंपरिक रूप से समाज में व्याप्त धारणाएं टूट रही हैं. फाइटर पायलट बनने से लेकर सशस्त्र सेनाओं तक महिलाओं की सफलता, बेटियों को कमतर आंकनेवालों के लिए बड़ा संदेश है. अगर बेटियों को अवसर मिलेंगे, तो निश्चित ही वे हर कदम पर साबित करेंगी- वे छोरों से कम नहीं हैं.

जिस तरह से महिलाएं साहसिक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रही हैं, उससे पारंपरिक रूप से समाज में व्याप्त धारणाएं टूट रही हैं.

व्यापार युद्ध के व्यापक नतीजे

अजीत रानाडे
सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन
editor@thebillionpress.org

बीते 19 मई को जब एग्जिट पोल ने एनडीए की भारी विजय की भविष्यवाणी की, तो मुंबई के शेयर बाजार ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए लंबी छलांग लगा कर उसे अपनी सलामी दी, मगर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग से लेकर शंघाई, सिंगापुर, सोल और सिडनी तक ये बाजार गिरे हुए थे. मध्य अप्रैल से इस क्षेत्र के शेयरों ने मिल कर अपनी कीमतों में 2.6 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान उठाया, जो भारत की राष्ट्रीय आय के बराबर है. हालांकि अभी मुंबई का शेयर बाजार जश्न के माहौल में है, पर यह लंबे वक्त तक इस एशियाई भय से बचा नहीं रह सकता. यह और बात है कि भारत में नयी सरकार का आर्थिक एजेंडा इस क्षेत्रीय अवसाद की एक हद तक भरपाई कर सकेगा. यह व्यापक भय दरअसल अमेरिका एवं चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध है, जो गुजरते वक्त के साथ संगीन ही हुआ जा रहा है.

यह सब तकरीबन एक साल पहले शुरू हुआ, जब अमेरिका ने चीनी स्टील और अमेरिका के मित्रों समेत कई देशों से आयात किये जाते एल्युमीनियम पर अचानक ही आयात शुल्क थोप दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि चीन अपने धातु उत्पादों पर सब्सिडी देकर उन्हें अमेरिकी उत्पादों से कृत्रिम सस्ता बनाये रखता है, जिससे अमेरिकी उद्योग एवं रोजगार को चोट पहुंचती है. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयात किये जानेवाले सोयाबीन तथा मोटर गाड़ियों पर आयात शुल्क मढ़ दिये. विशेषज्ञों एवं विश्लेषकों को लगा कि यह नूरा कुश्ती चल रही है, जो जल्द ही खत्म हो जायेगी. पर यह उम्मीद गलत ही साबित हुई और इसकी बजाय इस युद्ध ने और जोर पकड़ लिया.

अमेरिका ने लगभग 200 अरब डॉलर के चीनी आयातों पर आयात शुल्क 10 से 25 प्रतिशत तो बढ़ा ही दिये, यही दरें 350 अरब डॉलर के अन्य आयातों पर लगाने का इरादा व्यक्त करते हुए इसकी जद में तकरीबन पूरे चीनी आयात को ही ला देने की मंशा भी जतायी है. उसने चीन पर यह आरोप भी लगाया कि चीनी संयुक्त उद्यम अमेरिकी बौद्धिक संपदा चुरा रहे हैं. पिछले वर्ष अमेरिका ने सभी प्रौद्योगिक तथा चिप निर्माता कंपनियों को चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी 'जेडटीई' के साथ कारोबार करने से रोक दिया. हाल ही में यही रोक सुप्रसिद्ध चीनी कंपनी 'वाहवे' (जिसे सामान्यतः 'हुअवे' कह दिया जाता है) के साथ लगायी गयी है. अमेरिका के कहने पर कनाडा ने इस कंपनी के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया. इस पर भी लगे आरोप वैसे ही थे कि यह कंपनी अमेरिकी पेटेंट की रक्षा नहीं कर पा रही है और अपने 5जी हार्डवेयर में उसने जान-बूझ कर ऐसे फंदे लगा रखे हैं, जिन्हें पश्चिमी दुनिया अपनी सुरक्षा के लिए जोखिम मानती है.

यह सही है कि इनमें से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका है. इसका एक नतीजा तो यह हुआ कि गूगल ने यह साफ कर दिया है कि वह 'वाहवे' के फोनों पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे अपना संबल प्रदान नहीं करेगा. उधर चीन भी अपने फोनों से अमेरिकी जीपीएस प्रणाली को हटा कर उसके समानांतर एक चीनी सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम डालने पर विचार कर रहा है. कहने का तात्पर्य यह कि इन दोनों देशों के बीच एक प्रौद्योगिकीय युद्ध पूरे उफान पर है. पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के अधिकारी कहीं एक जगह बैठ इन विभेदकारी मुद्दों से पार पाने की कोई राह तलाश लेंगे. पर अब यह आशा धूमिल पड़ती जा रही है. चीन पर चोट करने की इस नीति से ट्रंप की घरेलू लोकप्रियता भी बढ़ रही है.

व्यापार युद्ध में आंख के बदले आंख की नीति में कोई भी विजेता नहीं होता. अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब अधिक कीमतें चुकानी होंगी, क्योंकि उन्हें सस्ते चीनी उत्पाद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे.

किंतु इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चीन एक समर्थ और सक्षम देश है, जो अमेरिका पर निर्भर नहीं है. चीन को यह भी पता है कि वह बेशकीमती चिपों के निर्माण में काम आनेवाले 'रेयर अर्थ' पदार्थों के 95 प्रतिशत उत्पादन को नियंत्रित करता है और वह बड़ी आसानी से अमेरिकी कंपनियों को इनकी बिक्री बंद कर सकता है. चीन ने चिप डिजाइन करनेवाली अपनी खुद की कंपनी भी विकसित कर ली है, जो कुछ ही वर्षों बाद इंटेल, क्वालकॉम एवं ऐसी अन्य कंपनियों की शक्ति का मुकाबला कर सकती है. कई वर्षों तक उसने अपने यहां गूगल, ट्विटर, जीमेल एवं ऐसी ही अन्य कंपनियों का इस्तेमाल बंद कर सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर के 'बैदु' एवं 'वीचैट' जैसे चीनी संस्करणों का विकास सुनिश्चित कर लिया. अलीबाबा, जो वस्तुतः एक बैंक भी है, अब अमेजोन का ताकतवर प्रतिद्वंद्वी बन चुका है. इसलिए ऐसा नहीं है कि चीनी इस प्रौद्योगिकीय शीत युद्ध को चुपचाप सहन कर लेंगे. अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने को चीन के हाथ में मौजूद एक अन्य हथियार यह भी है कि वह वैश्विक बांड बाजार में अमेरिकी ट्रेजरी बांड की बिक्री की बाढ़ ला दे. चीन के पास लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का विदेशी विनिमय भंडार संचित है, जो ज्यादातर अमेरिकी ट्रेजरी बांड की शक्ल में है. इन बांड के एक बड़े विक्रय का नतीजा यह होगा कि उनकी कीमतें धराशायी होते हुए अमेरिकी राजकोषीय स्थिति को गंभीर हानि पहुंचा सकती हैं. हालांकि, इस नुकसान से चीन भी बचा नहीं रह सकेगा, क्योंकि इन बांडों को बेचने से आयी आय की बनिस्बत उसके हाथ की इस दौलत की कीमत में गिरावट ज्यादा तेज होगी.

इस तरह के व्यापार युद्ध में आंख के बदले आंख की नीति में कोई भी विजेता नहीं होता. अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब अधिक कीमतें चुकानी होंगी, क्योंकि उन्हें सस्ते चीनी उत्पाद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे. वहां के करदाताओं को भी यह नागवार गुजरेगा, क्योंकि उनके कर से किसानों, खासकर सोया किसानों को मुआवजे दिये जायेंगे. संभव है, करों में बढ़ोतरी भी हो. वालस्ट्रीट के धराशायी हो जाने के कारण निवेशक भी नुकसान झेलेंगे. इस व्यापार युद्ध से ट्रंप के दुबारा जीतने की संभावनाएं जरूर बढ़ेंगी, पर इस अल्पावधि सियासी फायदे की कीमत बड़ी दीर्घावधि हानि से चुकानी होगी. भारत का अमेरिका के साथ खासा व्यापारिक अधिशेष (सरप्लस) है, अतः वह अमेरिकी बाजार को खोना गवारा नहीं कर सकता. इस व्यापार युद्ध में भारत किसी एक पक्ष का साथ देने को उसी तरह मजबूर हो सकता है, जिस तरह उसे ईरानी तेल के मामले में होना पड़ा. सो, ऐसे में, भारत को इस प्रौद्योगिकीय एवं व्यापार युद्ध में कई और नुकसान उठाने को तैयार रहना होगा.

(अनुवाद: विजय नंदन)

सांसद फंड छवि सुधार में बाधक

सुरेंद्र किशोर
वरिष्ठ पत्रकार
surendarkishore@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग के नये सांसदों को सदाचरण की सलाह दी है. यह बहुत अच्छी पहल है, पर क्या सांसद क्षेत्र विकास निधि के रहते इस तरह की कोई भी नसीहत कभी कारगर हो पायेगी? दरअसल, अधिकतर सांसदों की छवि को खराब करने में इस फंड का बड़ा योगदान है. लोग जानते हैं कि सांसद फंड में कैसी लूट मची रहती है? उस फंड से निर्मित संरचनाएं कितनी खराब होती हैं? कुछ ही सतर्क सांसद हैं, जो गुणवत्ता पर ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि वे नजराना नहीं लेते. इस फंड के उपयोग में लगातार जारी भ्रष्टाचार का प्रतिकूल असर प्रशासन की स्वच्छता पर भी पड़ रहा है. इस फंड के अधिकतर मामलों में कमीशन और रिश्वत की दर तय है. इसलिए दुरुपयोग व बदनामी के डर से कुछ राज्यसभा सदस्य आम तौर पर अपना पूरा फंड किसी विवि या किसी प्रतिष्ठित संस्थान को दे देते हैं. वहां किसी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत ही कम होती है.

आम चर्चा है कि बिहार में तो 40 प्रतिशत राशि संबंधित सरकारी ऑफिस ही ले लेता है. इसलिए सांसद फंड से निर्मित संरचनाएं सबसे कम टिकाऊ होती हैं. सबके अपने-अपने ठेकेदार हैं. वे उनके राजनीतिक कार्यकर्ता की भी भूमिका निभाते हैं. यह फंड राजनीति में वंशवाद को आगे बढ़ाने में भी काफी मददगार है. यदा-कदा राजनीतिक कार्यकर्ता तो टिकट के भी प्रत्याशी हो जाते हैं. कई सांसद ऐसा कोई 'खतरा' उपस्थित होने ही नहीं देते. पटना हाइकोर्ट ने 2003 में कहा था कि सांसद-विधायक कोटे का ठेका अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है. साल 2001 में सीएजी ने इस फंड में गड़बड़ी को पकड़ा था. चिंताजनक स्थिति यह है कि इस फंड के भ्रष्टाचार में नये-नये सेवा में आये कुछ अधिकतर आइएएस अफसर भी शामिल हो जाते हैं, यानी सांसद फंड देश के 'स्टिल फ्रेम' प्रशासन और उच्च स्तर की राजनीति में भ्रष्टाचार के रावण की नाभि का अमृत कुंड बन चुका है.

सांसद फंड के भ्रष्टाचार को लेकर वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2011 में ही इस फंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी. उससे पहले भी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व गैर-राजनीतिक हस्तियों ने इसे खत्म करने की सिफारिश की थी. यहां तक कि 2007 में लालू प्रसाद ने भी कहा था- 'सांसद-विधायक फंड समाप्त कर देना चाहिए. सांसद-विधायक फंड की ठेकेदारी के झगड़े के कारण ही हमारी सत्ता छिन गयी.' साल 2005 में सांसद फंड से रिश्वत लेने के आरोप में एक राज्यसभा सदस्य की सदस्यता भी जा चुकी है.

अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में भाजपा के 40 सांसद उनसे इस गंभीर मुद्दे पर मिले थे. उन्होंने आग्रह किया कि आप सांसद फंड बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके कारण भाजपा के अनेक कार्यकर्ता अब सांसद फंड के ठेकेदार बन रहे हैं. नतीजतन, उनकी आंखों में अब सेवा भाव नहीं, बल्कि वाणिज्यिक भाव देखे जा रहे हैं. इस बात से वाजपेयी जी भी चिंतित हो उठे और विचार शुरू कर दिया. इस बीच भाजपा के ही कुछ फंड समर्थक सांसदों को इसकी भनक लग गयी. दिल्ली के तब के एक चर्चित सांसद के नेतृत्व में करीब सौ सांसद प्रधानमंत्री से मिले. उन्होंने इसकी राशि और बढ़ा देने की गुजारिश की, तो वाजपेयी जी भी उनके दबाव में आ गये.

यह राशि 2003 में एक करोड़ रुपये सालाना से दो करोड़ रुपये कर दी गयी. जब अटल सरकार इस फंड की राशि बढ़ा रही थी, तो राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मनमोहन सिंह ने उसका सख्त विरोध करते हुए कहा था- 'यदि आप चीजों को इस तरह होने दीजियेगा, तो जनता नेताओं और लोकतंत्र में विश्वास खो देगी.' पर खुद प्रधानमंत्री के रूप में उस जनता की परवाह किये बिना मनमोहन सिंह ने 2011 में फंड को बढ़ा कर पांच करोड़ कर दिया था. कुछ साल पहले कांग्रेस सांसद और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा था- 'सांसद फंड पांच करोड़ से बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये कर देने से सांसद आदर्श ग्राम योजना को कार्यान्वित करने में सुविधा होगी.' यह अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इस फंड में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि 50 करोड़ रुपये की मांग लगभग सर्वदलीय है.

सांसद फंड की शुरुआत भी विवादास्पद स्थिति में 1993 में हुई थी. तब पीवी नरसिंह राव की सरकार अल्पमत में थी. संयोग है कि जब-जब सरकारें अल्पमत में थीं या मिली-जुली थीं, तभी फंड मिला और बढ़ा. संयुक्त संसदीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट 23 दिसंबर, 1993 को 3 बज कर 43 मिनट पर संसद में पेश की गयी. उसमें यह सिफारिश थी कि प्रत्येक सांसद को हर साल एक करोड़ रुपये का कोष दिया जाए, ताकि उससे वे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें. उस दिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह विदेश में थे. सरकार ने उसी दिन 5 बज कर 50 मिनट पर उस रपट को स्वीकार कर लिया. साल 1996 में मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि यदि मैं दिल्ली में होता, तो उस फंड को शुरू ही नहीं होने देता.

मौजूदा केंद्र सरकार अल्पमत में नहीं है. वह सांसद फंड खत्म करने का साहसिक कदम उठा सकती है. यह प्रशासनिक सुधार का हिस्सा होगा. अभी तो नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं. कोई सांसद उनके इस कदम का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करेगा. यदि प्रशासन व राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत पर हमला करना हो, तो प्रधानमंत्री इस फंड को यथाशीघ्र समाप्त करें.

मौजूदा केंद्र सरकार अल्पमत में नहीं है. वह सांसद फंड खत्म करने का साहसिक कदम उठा सकती है. यदि प्रशासन व राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत पर हमला करना हो, तो प्रधानमंत्री इस फंड को यथाशीघ्र समाप्त करें.

बोधि वृक्ष

हमारा अहंकार

जब पहल बार गैलीलियो ने कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है सूरज का, तो मनुष्य के अहंकार को बड़ा धक्का पहुंचा. धर्मगुरु ने कहा यह कैसे हो सकता है? परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को बनाया है. और सारा जगत मनुष्य के उपभोग के लिए बनाया है. तो जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, वह पृथ्वी सूरज के चक्कर कैसे लगा सकती है, सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी के. गैलीलियो को बुलाकर अदालत में कहा गया कि माफी मांग लो, ऐसी भूल की बातें मत करो. हजारों वर्षों से धार्मिक व्यक्ति यह कहते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किन्हीं और प्राणियों के बिना पूछे ही हम घोषणा करते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. न तो हमने चींटियों से पूछा है, न हमने पक्षियों से पूछा है. अपने ही मुंह से कहते रहे कि मनुष्य सरताज है सृष्टि का. दरअसल, हम अपने कोने में बैठे हुए घोषणाएं करते रहते हैं कि हम यह हैं, हम वह हैं. अगर पशु-पक्षियों से पूछा जाये और किसी दिन हम जान सकें कि वे क्या सोचते हैं, तो शायद ही कोई ऐसे प्राणी की जाति मिले, जो अपने मन में यह न सोचती हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं. चींटी सोचती होगी हम, बंदर सोचते होंगे हम. डार्विन ने कह दिया है कि मनुष्य विकसित हुआ है बंदरों से. अगर बंदरों से पूछा जाये, तो वे कभी यह मानने को राजी न होंगे कि आदमी उनके ऊपर एक विकास है. वे तो यही मानेंगे कि आदमी है, वह हमारा एक पतन है. हम दरख्तों पर कूदते, छलांगते हैं, आदमी जमीन पर सरकता है. यह हमारा पतन है, हमारी जाति से कुछ लोग पतित हो गये हैं नीचे और वे आदमी हो गये हैं. यह इवॉलूशन नहीं है. आदमी के अहंकार को जो भी चीज पुष्ट करती है, वह मानने को एकदम राजी हो जाता है. पृथ्वी केंद्र थी, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. लेकिन धीरे-धीरे, रोज-रोज ये बातें छिनती चली गयीं. विज्ञान ने रोज-रोज चोट की. पहली चोट यह हुई कि पृथ्वी केंद्र न रही, जिस दिन पृथ्वी केंद्र न रही, उसी दिन बहुत बड़ा धक्का मनुष्य के अहंकार को पहुंचा.

आपके पत्र

एसिड अटैक पर भी बने कड़ा कानून

एसिड अटैक की शिकार भागलपुर की मासूम-सी लड़की काजल अंततः जिंदगी की जंग हार गयी, पर शासन और समाज के समक्ष सवाल छोड़ गयी. और कितनी काजल जलेगी एसिड से? क्या वक्त नहीं आ गया कि निर्भया कांड के बाद जिस तरह से देश में बलात्कार के विरुद्ध जन संघर्ष छिड़ा और सरकार ने संविधान में आवश्यक संशोधन करते हुए कुछ मजबूत निर्णय लिए, न्यायालय ने भी उचित संज्ञान लिया, उसी प्रकार अब एसिड अटैक को भी क्रूरतम अपराध की श्रेणी में ला दोषियों को आजीवन कारावास अथवा सजा-ए-मौत दी जाए? बलात्कार की तरह एसिड अटैक के केस में भी हमला सिर्फ लड़कियों के शरीर पर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और उनके वजूद पर होता है. यह हत्या से बड़ा संगीन अपराध है, क्योंकि हत्या में मौत एक बार आती है, जबकि बलात्कार और एसिड हमले की पीड़िता आजीवन हर दिन और हर पल मरती है. घुट-घुट कर जीती है. जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है.

सुरजीत झा, गोड्डा

एवरेस्ट यात्रा का विशेष नियम नहीं

अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बारे में बहुत ही चौंकाने और स्तब्ध कर देने वाला समाचार आया. दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर इतनी भीड़ जमा हो गयी है कि वहां जाम की स्थिति पैदा हो गयी है. इससे लोगों को इस सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने के लिए कई-कई घंटे इंतजार करने पड़ा और इससे उनके पास उपलब्ध ऑक्सीजन समाप्त हो गयी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. अनुभवी पर्वतारोही विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए नेपाल सरकार के पास कोई विशिष्ट नियम नहीं है और न ही पर्वतारोहियों की संख्या को नियंत्रित करने का कोई स्वीकृत विधान. उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-अधिक पर्वतारोहियों से ज्यादा-से-ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करना रह गया है. यह हिमालय, ग्लेशियरों, वहां से निकलने वाली नदियों के लिए और उन पर आश्रित अरबों लोगों के लिए बहुत ही दुखद है.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

अब जनप्रतिनिधि से काम कराएं

अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. देश में सभी को अपना जनप्रतिनिधि मिल चुका है. समय आ गया है कि अपने क्षेत्र विशेष की सभी समस्याओं के समाधान के लिए चुने गये जनप्रतिनिधियों से बेझिझक होकर कहें. इन जनप्रतिनिधि के पास पूरा समय है और वे आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. अभी उनके पास पूरे पांच साल हैं. जब यकीन हो जाए कि आपके चुने गये जनप्रतिनिधि आपकी समस्या के समाधान के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं या काम नहीं करना चाहते, तो यह हक है कि आप इसके लिए किसी दूसरी पार्टी के सक्रिय नेता से संपर्क करें. एक बात और, काम करवाने के लिए पहले एक संस्था बना लें, जिससे जनप्रतिनिधियों को यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस क्षेत्र में कौन-सा काम करना है.

पालूराम हेंब्रम, सालगझारी, जमशेदपुर

कुछ अलग

शगुन में शोर

मिथिलेश कु. राय
युवा रचनाकार
mithileshray82@gmail.com

कक्का एक दिन यह कह रहे थे कि आनेवाले दिनों में ध्वनि-प्रदूषण के सामने सारे प्रदूषण बौने साबित हो जायेंगे और लोग स्थिर दिमाग से कुछ भी सोचने-समझने के लिए फिर से कंदराओं की तरफ भागने के बारे में सोचने लगेंगे. वह समय मनुष्य के पागल हो जाने का समय होगा. घर के बाहर उसे सबसे अधिक शोर से ही मुठभेड़ करनी होगी और जब वह घर पहुंचेगा, तब भी वह चारों ओर से आ रहे शोर को रोकने के प्रयास में विफल होगा. मनुष्य-जीवन में चैन की नींद तब बीते जमाने की बात हो जायेगी और वह कहीं भी शांति से दो पल बैठने की कल्पना तक नहीं कर सकेगा.

वसंत पंचमी के दिनों की बात है. कक्का का मन उखड़ा हुआ था. इस मौसम में तो मैंने उन्हें चिड़ियों की तरह गाते हुए सुना था. वे बस खेत और खेत में लगी फसलों के बारे में बताते थे. वसंत के मौसम में खेत में फसल रंग-बिरंगे फूलों से आच्छादित हो रहे होते हैं, वे उसकी बातें करते थे. लेकिन उस दिन वे शोर की बातें लेकर बैठ गये थे और बड़े खिन्न नजर आ रहे थे. उनकी आंखें लाल थीं. ऐसा लग रहा था कि वे रातभर सो नहीं पाये हों और दिन में भी उन्हें चैन न मिला हो.

कक्का ने भेद खोला. इलाके में दर्जनों जगह कार्यक्रम हो रहे थे. एक-एक जगह पर चार-चार लाउडस्पीकर लगाकर फुल साउंड में भजन बजाया जा रहा था. लोगों के कान सुन्न हो रहे थे. एक आदमी एक कान में अंगुली डाल कर दूसरे कान से मोबाइल लगाये कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन फिर भी कुछ सुन नहीं पा रहा था. बस वह इस तरफ से हैलो-हैलो करता जा रहा था. वह झल्ला रहा था. तब मेरा भी क्रोध बढ़ गया कि भक्ति की यह कौन सी धारा है, जिसमें समर्पण नहीं, सिर्फ कानफोड़ू संगीत ही शेष बच गया है!

साउंड के बढ़ते प्रचलन से कक्का को लगन के दिनों की याद आ गयी. कहने लगे कि अब शादी-ब्याह के मौसम को ही देख लो, ब्याह में पहले से मौजूद कुरीतियों को दूर करने की अपेक्षा उसे और अधिक खर्चीला बना दिया गया है. बारात-भोज पर पुनर्विचार करने की जरूरत थी. लेकिन अब तो इन अवसरों पर बारातियों की सवारियों का एक लंबा रैला भी शामिल हो गया है. बारात के द्वार पर आते ही पटाखों की गूंज से इलाके देर तक थर्राये रहते हैं. डीजे की भयंकर आवाज देर रात तक शांति चौपट कर देती है और बुजुर्गों की धड़कन को बढ़ाती रहती है. अब तो जरा-जरा सी बात पर लोग चार-चार लाउडस्पीकर बजाते हैं. बेकार में क्यों यह बजता ही जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं रह गया है.

कक्का को यह शक है कि अगर लोगों की ऐसी ही मानसिकता बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब ध्वनि-प्रदूषण के आगे सारे प्रदूषण पानी भरते नजर आयेंगे. तब वह बड़ा ही दयनीय समय होगा. तब हो सकता है कि हमारे पास साफ पानी हो, शुद्ध हवा भी हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन इतना विचलित रहेगा कि हम ढंग से सोने, सोचने और तन्मय होकर काम करने के बारे में सिर्फ कल्पना ही कर पायेंगे!

देश दुनिया से

जर्मनी में सौ साल की महिला नगर पार्षद

कहते हैं राजनीति में उतरने की कोई उम्र नहीं होती. जर्मनी की एक महिला ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है. सौ साल की लिजेल हाइजे जर्मनी के एक छोटे से शहर किर्षहाइमबोलांडेन से नगर पार्षद चुनी गयी हैं. उस शहर में मात्र आठ हजार लोग रहते हैं. दरअसल, लिजेल हाइजे को स्विमिंग का काफी शौक है. जब स्थानीय सरकारी स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया, तो उसे दोबारा खुलवाने के इरादे से लिजेल चुनाव में खड़ी हो गयीं. इस वृद्ध महिला के दृढ़निश्चय को देखते हुए शहर के लोगों ने बढ़-चढ़ कर उन्हें वोट दिया. लिजेल शहर के एक संगठन 'वियर फ्यूर कीबो' यानी 'किर्षहाइमबोलांडेन के लिए हम' के साथ जुड़ी हुई हैं. अब वे नगरपालिका में इस संगठन की प्रवक्ता के रूप में मौजूद होंगी. अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव की पैरवी करने का उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता है. लिजेल ब्रेक्जिट का समर्थन नहीं करती हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बड़ी फैन हैं. वे एकजुट यूरोप में विश्वास रखती हैं. राजनीति में हो रहे बदलावों के बारे में वे कहती हैं कि राजनीति मानवतावाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ चुकी है. अब नगर पार्षद बन जाने के बाद वे सबसे पहले स्विमिंग पूल का मुद्दा उठानेवाली हैं.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है